



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-31032020-218973
CG-MH-E-31032020-218973

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2020/चैत्र 11, 1942

No. 139]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2020/CHAITRA 11, 1942

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

(मा.सं.प्र विभाग)

(बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर)

अधिसूचना

मुंबई, 31 मार्च, 2020

सं. बीसीसी/एचआरएम/ईएक्सई/112/274.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल ने केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के पश्चात और भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श में एतद्वारा बैंक ऑफ़ बड़ौदा (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाया है, अर्थात् :-

- (1) ये विनियम बैंक ऑफ़ बड़ौदा (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2020 कहलाएंगे.
- (2) ये विनियम रक्षित अन्यथा प्रदान किए गए अनुसार, उन्हें नवंबर 2012 के पहले दिन से प्रभावी माना जाएगा.
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में (इसमें इसके पश्चात कथित विनियमन के रूप में संदर्भित), विनियमन 3 में, खंड (एफ) में निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(एफ) “‘परिवार’ से अभिप्राय अधिकारी की पत्नी/पति, अधिकारी पर पूर्ण रूप से आश्रित अविवाहित बच्चे (जिसमें सौतेले एवं कानूनन गोद लिये गये बच्चे भी शामिल हैं), 40% या अधिक की दिव्यांगता वाले दिव्यांग भाई/बहन, विधवा पुत्री और आश्रित तलाकशुदा या अलग रह रही पुत्री, बहन जो अविवाहित हो या पति से अलग या तलाकशुदा या परित्यक्ता हो या विधवा बहन और विवाहित महिला अधिकारी के मामले में अपने नैसर्गिक माता-पिता या सास-ससुर, लेकिन दोनों नहीं, से है.

स्पष्टीकरण : “पूर्ण रूप से आश्रित” से अभिप्राय परिवार के ऐसे सदस्य से है जिनकी आय रु.10000/- प्रतिमाह से अधिक न हो और यदि पूर्णतः आश्रित परिवार के सदस्य माता-पिता हैं तो किसी एक की मासिक आय या माता-पिता दोनों की सकल आय रु. 10000 प्रति माह से अधिक है तो दोनों माता-पिता अधिकारी पर पूर्ण रूप से आश्रित नहीं माने जाएंगे।

3. उप-विनियमन (6) के लिए कथित विनियम के विनियमन 4 में, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

(6) 1.11.2012 से प्रत्येक श्रेणी के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होंगे:

क. उच्च कार्यपालक श्रेणी:

वेतनमान VII – रु. 76520 –2120/4-85000

वेतनमान VI - रु. 68680-1960/4-76520

ख. वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान V – रु. 59170-1650/2-62470-1800/2-66070

वेतनमान IV – रु. 50030-1460/4-55870-1650/2-59170

ग. मध्य प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान III – रु. 42020-1310/5-48570-1460/2-51490

वेतनमान II – रु. 31705-1145/1-32850-1310/10-45950

घ. कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी:

वेतनमान I – रु. 23700-980/7-30560-1145/2-32850-1310/7-42020

स्पष्टीकरण : 31.10.2012 से प्रभावी वेतनमान जिस अधिकारी पर भी लागू होते हैं उसे 01.11.2012 के इस उप विनियम के अनुसार चरणवार निर्धारित वेतनमान में नियत किया जाएगा अथवा संबंधित वेतनमान में प्रथम चरण से तदनु रूप चरण पर तथा जहां यदि अन्यथा न दिया गया हो तो वेतनवृद्धि सामान्यतः वर्ष पूर्ण होने की तिथि पर ही देय होगी।

(7) उप विनियमन (1), (2), (3), (4), (5) और (6) में उल्लिखित किसी भी बात का आशय यह नहीं होगा कि बैंक पूरे समय इन श्रेणियों में अधिकारियों को सेवारत रखे।

(8) 1.11.2012 से अधिकारियों को विशेष भत्ता का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा :

वेतनमान श्रेणी I-III - मूल वेतन का 7.75% + उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान श्रेणी IV-V- मूल वेतन का 10% + उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान श्रेणी VI-VII- मूल वेतन का 11% + उस पर लागू महंगाई भत्ता

(9) मार्च 2020, के 31 वें दिन को और इसके बाद शीर्ष कार्यपालक श्रेणी में मुख्य महाप्रबंधक के पद के लिए वेतनमान और विशेष भत्ता निम्नानुसार होगा:

(ए) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी

स्केल VIII = रु. 1,03,000 - 2,700/3 - 1,11,100 - 2,800/1 - 1,13,900

(बी) विशेष भत्ता

स्केल VIII = मूल वेतन का 11% + लागू महंगाई भत्ता:

बशर्ते कि इस उप-विनियमन में उल्लिखित किसी भी बात का आशय यह नहीं होगा कि बैंक पूरे समय इन श्रेणियों में अधिकारियों को सेवारत रखे।

नोट: इसमें विशेष महंगाई भत्ते के साथ उप-विनियमन (8) और (9) में निर्दिष्ट विशेष भत्ते को अधिवर्षिता लाभ अर्थात् न्यू पेंशन स्कीम, प्रोविडेंट फंड और ग्रेज्युटी के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा."

4. कथित विनियम के विनियमन 5 में, -

i. उप-नियमन (1) के लिए निम्नलिखित उप-विनियमन प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

“(1) दिनांक **01.11.2012** को और उसके बाद से विनियम 4 के उप विनियम (6) के प्रावधानों के अधीन वेतनवृद्धियाँ निम्नलिखित के अधीन मंजूर की जाएंगी, अर्थात्:-

ए. विनियम 4 के उप विनियम (6) में वर्णित विभिन्न वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धियाँ, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन वार्षिक आधार पर देय होंगी और जिस महीने में यह देय होती हों उस महीने की पहली तारीख को दी जाएंगी।

बी. वेतनमान I और वेतनमान II के अधिकारियों को अपने संबंधित वेतनमान में अधिकतम वेतनमान तक पहुँचने के एक साल बाद खंड (सी) में निर्दिष्ट अनुसार अगले उच्च वेतनमान में अवरुद्ध वेतनवृद्धि सहित और वेतन वृद्धि दी जाएगी बशर्ते कि उन्होंने दक्षता सीमा को पार किया है;

सी. कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I का अधिकारी जो विनियम (सी) के अनुरूप अधिकतम वेतनमान तक पहुँचने के पश्चात मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतन मान II में पहुँचा है, वह प्रत्येक 3 वर्षों की सेवा पूरी होने पर चार अवरुद्ध वेतनवृद्धियों के लिए पात्र होगा जो रु.1310/- की दो वेतनवृद्धियाँ तथा उसके बाद रु.1460/- की दो वेतनवृद्धियाँ होंगी.

डी. मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान-II का अधिकारी जो विनियम (बी) के अनुरूप अधिकतम वेतनमान तक पहुँचने के पश्चात मध्य प्रबंधन श्रेणी-III के वेतनमान में पहुँचा है वह प्रत्येक तीन साल की सेवा पूरा करने पर रु.1460/- की तीन अवरुद्ध वेतनवृद्धियों के लिए पात्र होगा और तीसरी अवरुद्ध वेतनवृद्धि के 2 वर्ष के बाद चौथी अवरुद्ध वेतनवृद्धि रु. 1460/- के लिए पात्र होगा.

बशर्ते कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने तीसरी अवरुद्ध वेतनवृद्धि के बाद दो वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है वे 01.05.2015 से चौथी अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे.

ई. अधिष्ठायी मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III में अधिकारीगण (जो मध्य प्रबंधन श्रेणी/वेतनमान III में भर्ती हुए हैं अथवा पदोन्नत हुए हैं) प्रत्येक तीन साल की सेवा पूर्ण करने बाद प्रत्येक रु.1460/- की तीन अवरुद्ध वेतनवृद्धियों के पात्र होंगे और जिन अधिकारियों ने 01/05/2015 तक तीसरी अवरुद्ध वेतनवृद्धि प्राप्त होने के दो वर्ष या उसके बाद रु.1460/- की चौथी वेतनवृद्धि और चौथी वेतनवृद्धि प्राप्त होने के दो वर्षों के बाद रु.1460/- की पाँचवी अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि जिस अधिकारी ने चौथी अवरुद्ध वेतनवृद्धि के बाद दो वर्ष पूरे कर लिए हैं उसे 01.05.2015 से पाँचवी अवरुद्ध वेतनवृद्धि प्राप्त होगी.

एफ़. दिनांक 01.05.2015 से वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी/वेतनमान -IV के अधिकारी अधिकतम वेतनमान तक पहुँचने के तीन वर्षों के बाद रु.1650/- की एक अवरुद्ध वेतनवृद्धि प्राप्त करने के पात्र होंगे.

बशर्ते कि इस तरह की वेतनवृद्धियाँ उन अधिकारियों को नहीं दी जाएंगी जिन्होंने पदोन्नत किए जाने पर पदोन्नति लेने से मना कर दिया है.

स्पष्टीकरण : - इस उप-नियमन के तहत अगले उच्च वेतनमान में ऐसी वेतनवृद्धि की मंजूरी पदोन्नति के लिए नहीं है और अधिकारियों के विशेषाधिकार, परिलब्धियाँ, कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ उनके मूल पदों के रूप में जारी रहेगी.”

(ii) उप-नियमन (2), स्पष्टीकरण में, खंड (एफ) के बाद और नोट से पहले, निम्नलिखित खंड को प्रविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

“जी. **01.11.2012** को और उसके बाद से अन्य सारी चीजों के समान रहने पर व्यावसायिक योग्यता भत्ता को निम्न तालिका के अनुसार संशोधित किया गया है :

तालिका

जिन्होंने जूनियर एसोशिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक्स (जेएआईआईबी) या सर्टिफाइड एसोशिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक्स (सीएआईबी) – पार्ट I उत्तीर्ण किया है	(i) अधिकतम वेतनमान तक पहुँचने के एक वर्ष पश्चात रु.670/- प्रति माह
जिन्होंने सर्टिफाइड एसोशिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक्स (सीएआईआईबी) के दोनों भाग उत्तीर्ण किए हैं :	(i) अधिकतम वेतनमान तक पहुँचने के एक वर्ष पश्चात रु.670/- प्रति माह (ii) अधिकतम वेतनमान तक पहुँचने के दो वर्ष पश्चात रु.1680/- प्रति माह.

बशर्ते कि अगर कोई अधिकारी जेएआईआईबी/ सीएआईआईबी परीक्षा (कोई एक भाग/ दोनों भाग) अपने वेतनमान की उच्चतम सीमा पर पहुँचने के बाद पास करता है, उसे उस दिन, जिस दिन उसने उक्त योग्यता प्राप्त की है, से व्यावसायिक योग्यता भत्ता की पहली किस्त देय होती है और व्यावसायिक योग्यता भत्ता की अगली किस्त व्यावसायिक योग्यता भत्ता की पहली किस्त प्राप्त होने की तारीख से संदर्भित होगी।”

(iii) उप-नियमन (3) में, खंड (ई) के तहत तालिका के बाद, निम्नलिखित प्रविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

“(एफ) 1 नवंबर, 2012 को और उसके बाद से अन्य चीजों के समान होने पर स्थायी वैयक्तिक भत्ता के साथ-साथ आवास भत्ता निम्नलिखित दर पर होगा और सेवा की पूरी अवधि के लिए नियत रहेगा.

तालिका

वेतनवृद्धि घटक (रु.)	01.11.2012 से वेतनवृद्धि घटक पर महंगाई भत्ता (रु.)	जहां बैंक का आवास उपलब्ध कराया जाता है वहां कुल स्थायी वैयक्तिक भत्ता (रु.)
(1)	(2)	(3)
1310	143	1453
1460	159	1619
1650	180	1830
1800	196	1996
1960	214	2174
2120	231	2351

नोट:

- इस उप-विनियमन (3) के खंड (बी), (सी), (डी), (ई) और (एफ) के कॉलम (3) में उल्लिखित अनुसार स्थायी वैयक्तिक भत्ता या स्थायी वैयक्तिक वेतन ऐसे अधिकारियों को दिया जाएगा जिन्हें बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है.
- आवास भत्ता पाने के पात्र अधिकारियों के लिए स्थायी वैयक्तिक भत्ता या स्थायी वैयक्तिक वेतन खंड (एफ) के तहत की तालिका के कॉलम (1) एवं (2) में विनिर्दिष्ट राशि तथा विनियमन 4 के उप-विनियमन (2), (3), (4), (5), और (6) में विनिर्दिष्ट संबन्धित वेतनमान की अंतिम वेतनवृद्धि के समय संबन्धित अधिकारी द्वारा लिए जा रहे आवास भत्ते की राशि का कुल जोड़ होगा.
- केवल ऐसे अधिकारी जो बैंक की सेवा में 1 नवंबर, 1993 को या उससे पहले थे, वे अपने संबन्धित वेतनमान में अधिकतम वेतनमान तक पहुँचने के एक वर्ष पश्चात स्थायी वैयक्तिक वेतन पाने के लिए पात्र होंगे.

(iv) 1 नवंबर, 1999 को और उसके बाद से स्थायी वैयक्तिक वेतन के जारी होने के कारण उप विनियमन (2) की व्याख्या (सी) के अनुसार व्यावसायिक योग्यता भत्ता के जारी होने की समयावधि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा.

बशर्ते कि पहले के प्रावधानों के कारण यदि व्यावसायिक योग्यता भत्ता से संबंधित कोई किस्त एक वर्ष आगे बढ़ जाती है और जो 01 नवंबर, 1999 को या उसके बाद जारी होनी है तो यह संबंधित अधिकारी को इसी दिन जारी होगी और व्यावसायिक योग्यता भत्ता की दूसरी किस्त, यदि कोई हो, 01 नवंबर, 2000 को जारी होगी.

(v) स्थाई वैयक्तिक भत्ता या स्थाई वैयक्तिक वेतन के वृद्धि घटक को अधिवर्षिता लाभ के लिए पात्र माना जाएगा

(vi) ऐसे अधिकारी जिन्होंने उपर्युक्त खंड (ए) में उल्लिखित अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धि ले ली हो वे अधिकतम वेतनमान में पहुंचने के एक वर्ष पश्चात उपर्युक्त खंड (बी), (सी), (डी), (ई) या (एफ) में उल्लिखित अनुसार स्थाई वैयक्तिक भत्ता या स्थाई वैयक्तिक वेतन प्राप्त करेंगे.

(जी) मार्च 2020 के 31 वें दिन को और उसके बाद से अन्य चीजों के समान होने पर स्थायी वैयक्तिक भत्ता के साथ-साथ आवास भत्ता, यदि कोई हो, उच्च कार्यपालक श्रेणी वेतनमान-VIII में मुख्य महाप्रबंधक प्रबंधक के पद के लिए, निम्नलिखित दर पर होगा और सेवा की पूरी अवधि के लिए नियत रहेगा:

तालिका

वेतनवृद्धि घटक (रु.)	वेतनवृद्धि घटक पर महंगाई भत्ता (रु.)	जहां बैंक का आवास उपलब्ध कराया जाता है वहां कुल स्थायी वैयक्तिक भत्ता (रु.)
(1)	(2)	(3)
2800	305	3105

5. विनियमन 7 के लिए, निम्नलिखित विनियमन को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“7. वर्गीकरण — (1) मार्च 2020 के 31 वें दिन को और उसके बाद से और विनियमन 6 के प्रावधानों के अधीन, बैंक में अधिकारियों के विभिन्न पदों को निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

तालिका

पद	श्रेणी या वेतनमान जिसमें रखा गया है
मुख्य महाप्रबंधक	उच्च कार्यपालक श्रेणी वेतनमान-VIII
महाप्रबंधक	उच्च कार्यपालक श्रेणी वेतनमान -VII
उप महाप्रबंधक	उच्च कार्यपालक श्रेणी वेतनमान -VI
सहायक महाप्रबंधक	वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान -V
मुख्य प्रबंधक	वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान -IV
वरिष्ठ प्रबंधक	मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान -III
प्रबंधक	मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान -II
अधिकारी अथवा उप प्रबंधक	कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान -I

(2) यदि उपरोक्त वर्गीकरण से कोई कठिनाई या विसंगति उत्पन्न होती है, तो इसे प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी और ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से संबंधित समिति के पास भेजा जाएगा जो इस निर्णय के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं.”

6. कथित विनियमन के विनियमन 21 में, उप-विनियमन (5) के बाद, निम्नलिखित विनियमन को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(6) दिनांक 1.11.2012 को तथा इसके बाद से, महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960=100 के तिमाही औसत में 4440 पाइंट के ऊपर चार पाइंट की प्रत्येक वृद्धि अथवा गिरावट के हिसाब से वेतन के 0.10% की दर से देय होगा..

स्पष्टीकरण.— इस उप-विनियमन के उद्देश्य के लिए,—

- (ए) महंगाई भत्ते के लिए “वेतन” से आशय अवरुद्ध वेतन वृद्धियों और विशिष्ट भत्ते सहित मूल वेतन से है;
- (बी) व्यावसायिक योग्यता भत्ता/ व्यावसायिक योग्यता वेतन जैसा कि विनियम 5 के उप-विनियमन (2) में स्पष्टीकरण के खंड (सी), (डी), (ई), (एफ) और (जी) में विनिर्दिष्ट किया गया है, महंगाई भत्ते हेतु गणना में लिया जाएगा”.

7. कथित विनियमन के विनियमन 22 में,—

(i) उप-विनियमन (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियमन को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(ए) यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो वह जिस वेतनमान में है उस वेतनमान के प्रथम चरण का 0.75 प्रतिशत वेतन या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा;

(बी) यदि अधिकारी को बैंक द्वारा मकान नहीं दिया जाता है, तो दिनांक 01.11.2012 को तथा उसके बाद से वह निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट दरों पर मकान किराया भत्ता के लिए पात्र होगा:—

तालिका

कार्यस्थल	मकान किराया भत्ता
(1)	(2)
(i) प्रमुख “ए” वर्ग के नगर तथा समूह ए के प्रोजेक्ट एरिया केन्द्र	वेतन का 9.0%
(ii) क्षेत्र I में अन्य स्थान तथा समूह बी के प्रोजेक्ट एरिया केन्द्र तथा गोवा राज्य	वेतन का 8.0%
(iii) अन्य स्थान	वेतन का 7.0%

बशर्ते कि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उसके प्रथम चरण के वेतन के 0.75 प्रतिशत से ऊपर, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया देय होगा जो ऊपर कॉलम (2) में दर्शायी गयी दरों के अनुरूप देय मकान किराया भत्ते का अधिकतम 150 प्रतिशत होगा.

नोट: अधिकारी के अपने स्वामित्व वाले आवास की लागत से जुड़े मकान किराया भत्ते के दावे भी अभी तक के समान मकान किराया भत्ता का 150 प्रतिशत तक सीमित होंगे.”;

(ii) उप-विनियमन 2 हटा दिया जाएगा.”.

8. कथित विनियमन के विनियमन 23 में,—

(ए) उप-विनियमन (1), (2), (3), (4) एवं (5) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियमन को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(1) दिनांक 1.11.2012 को और उसके बाद से यदि अधिकारी निम्नलिखित तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित किसी स्थान पर कार्यरत है तो वह उस स्थान के सामने कॉलम (2) में उल्लिखित दर पर शहर प्रतिपूरक भत्ता पाने का पात्र होगा:—

तालिका

स्थान	दर
(1)	(2)
(i) क्षेत्र I और गोवा राज्य के स्थान	मूल वेतन का 4% जो अधिकतम रु. 870/- प्रतिमाह के अधीन होगा
(ii) पांच लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान और राज्यों की राजधानियां तथा चंडीगढ़, पुदुचेरी और पोर्ट ब्लेयर.	मूल वेतन का 3% जो अधिकतम रु. 600/- प्रतिमाह के अधीन होगा

- (2) दिनांक 1.11.2012 और उसके बाद से, विशेष क्षेत्र भत्ते की दरें इन विनियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की जाएंगी.
- (3) दिनांक 1.11.2012 और उसके बाद से यदि कोई अधिकारी ऐसे क्षेत्र में सेवारत है जिसे समूह 'ए' या समूह 'बी' के अंतर्गत आने वाले प्रोजेक्ट एरिया के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है तो वह समूह 'ए' के लिए रु. 400/- प्रतिमाह और समूह 'बी' के लिए रु. 350/- प्रतिमाह की दर से प्रोजेक्ट एरिया प्रतिपूरक भत्ता पाने के लिए पात्र होगा.
- (4) दिनांक 1.6.2015 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को शैक्षिक वर्ष के बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है, और यदि उसके एक या एक से अधिक बच्चे पूर्ववर्ती स्थान पर विद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं तो जिस तारीख को अधिकारी नई जगह पर रिपोर्ट करता है, उस तारीख से उसे शैक्षिक वर्ष के अंत तक, सभी बच्चों के लिए रु. 1100/- प्रति माह मध्य शैक्षिक वर्ष स्थानांतरण भत्ता दिया जाएगा परंतु यदि उसके सभी बच्चे पूर्ववर्ती स्थान पर अध्ययन करना बंद कर देते हैं तो यह भत्ता मिलना बंद हो जाएगा.
- (5) दिनांक 1 जून 2015 को और उसके बाद से यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर किसी सेवा के लिये प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह प्रतिनियुक्ति के पद पर देय परिलब्धियों को प्राप्त करने के लिए अपना विकल्प दे सकता है अथवा वह विकल्प के रूप में अपने वेतन के अतिरिक्त वेतन का 7.75% अधिकतम रु. 4000/- प्रति माह के अध्यधीन प्रतिनियुक्ति भत्ता और ऐसे अन्य भत्ते ले सकता है जो उसे उसी स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने की स्थिति में मिलते.

बशर्ते कि उसकी प्रतिनियुक्ति से पूर्व उसकी तैनाती के स्थान पर ही स्थित किसी संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उसे उसके वेतन का 4% अधिकतम रु.2000/- प्रति माह के अध्यधीन प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा.

बशर्ते कि किसी अधिकारी को बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है उसे उसके वेतन का 4% अधिकतम रु. 2000/- प्रति माह प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा.

(बी) उप-विनियमन (8) के लिए निम्नलिखित उप विनियमन प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा:-

“(8) दिनांक 1 नवंबर 2012 को और उसके बाद से यदि उसका कार्य-समय दिन के दो भागों में बंटा हुआ है और कार्य समय के इस विभाजन में कम से कम दो घंटे का अंतराल है तो उसे रु.200/- प्रति माह विभाजित कार्य-समय भत्ता दिया जाएगा.”

(सी) उप-विनियमन (10) में के अनुसार:

(ए) अंकों, अक्षरों और शब्दों के लिए “नवंबर 2007 की पहली तारीख”, के स्थान पर “नवंबर 2012 की पहली तारीख”, अंकों, अक्षरों और शब्दों में प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(बी) टेबल के लिए, निम्नलिखित टेबल प्रतिस्थापित होगा, यथा:-

स्थान	दर
(1)	(2)
i. 1000 मीटर और उससे अधिक परंतु 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान और मेरकरा नगर	वेतन का 2% अधिकतम 750/- प्रति माह के अध्यक्षीन
ii. 1500 मीटर और उससे अधिक परंतु 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाला स्थान	वेतन का 2.5% अधिकतम 1000/- प्रति माह के अध्यक्षीन
iii. 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाला स्थान	वेतन का 5% अधिकतम 2000/- प्रति माह

9. कथित विनियम के विनियमन 24 के अनुसार:-

(i) उप-विनियमन (1), के लिए निम्नलिखित उप-विनियमन प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा:-

“(1) दिनांक 01 नवंबर 2012 को और उसके बाद से अधिकारी स्वयं और अपने परिवार हेतु चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए निम्नलिखित तालिका में उल्लेख किए गए अनुसार दावा की गई राशि के लिए खातों की विवरणी के साथ ऐसा व्यय करने के स्वयं के स्व-प्रमाणपत्र के आधार पर पात्र होगा, यथा:-

तालिका

श्रेणी	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष
(1)	(2)
कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी और मध्य प्रबंधन श्रेणी	रु.8000/- या व्यय की गई राशि, जो भी कम हो
वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी और उच्च कार्यपालक श्रेणी	रु.9050/- या व्यय की गई राशि, जो भी कम हो

नोट:-

(i) अप्रयुक्त चिकित्सा सहायता संचित करने की अनुमति अधिकारी को दी जा सकती है परंतु वह किसी भी समय ऊपर दी गई अधिकतम राशि के तीन गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए या;

(ii) वर्ष 2012 के लिए, चिकित्सा सहायता योजना के तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति 2 महीने, अर्थात् नवंबर, 2012 और दिसंबर 2012 के लिए समानुपातिक रूप में बढ़ाई जाएगी.

(1ए) कोई अधिकारी निदेशक मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट नियम एवं शर्तों के अनुसार अपने और अपने परिवार के लिए चिकित्सा बीमा सुविधा के लिए पात्र होगा

10. कथित विनियम के विनियमन 25 में, उप विनियम (2) के लिए निम्नलिखित उप-विनियमन प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा:-

“(2) उप-विनियम (1) में निहित कुछ भी के नहीं होते हुए भी यदि बैंक चाहे तो अधिकारी को आवास उपलब्ध करा सकता है जिसके लिए अधिकारी दिनांक 01 नवंबर 2012 को और इसके बाद से अपने वेतनमान के प्रथम स्तर के 0.75% के समान या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, का भुगतान करेगा:

बशर्ते यदि ऐसे आवास पर अधिकारी को फर्नीचर भी उपलब्ध कराया गया हो तो उनके वेतनमान के प्रथम स्तर के मूल वेतन का 0.15% के बराबर अतिरिक्त राशि उनसे वसूल की जाए.

बशर्ते यह भी कि जहां बैंक द्वारा ऐसी आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है, तो बिजली, पानी, गैस और सफाई प्रभार, अधिकारी द्वारा वहन किए जाएंगे।

11. कथित विनियम के विनियमन 33 में, उप विनियम (4) के लिए निम्नलिखित उप-विनियमन प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा:-

“(4) दिनांक 01 जून 2015 को और उसके बाद से ऐसी स्थिति को छोड़कर जहां अवकाश के लिए आवेदन किया गया है और उसे अस्वीकृत कर दिया गया हो, अधिकतम 270 दिन तक का अर्जित अवकाश ही संचित किया जा सकेगा।

तथापि, अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सीमा अधिकतम 240 दिनों की होगी।

अर्जित अवकाश लेने के इच्छुक अधिकारी सामान्यतः ऐसा अवकाश लेने के अपने आशय की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व देंगे।

12. कथित विनियम के विनियमन 34 में, उप विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियमन शामिल किया जाएगा, यथा:-

“(4) दिनांक 1 जून 2015 से किडनी/ अंग दान करने के लिए अधिकारी कर्मचारी की पूरी सेवा अवधि के दौरान उन्हें 30 दिनों तक की विशेष बीमारी अवकाश स्वीकृत की जा सकती है।”

13. कथित विनियम के विनियमन 36 में, उप विनियम (2) और (3) के लिए निम्नलिखित उप-विनियमन प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा:-

“(2) 25 मई 2015 से, निःसंतान महिला अधिकारी के 1 वर्ष से कम उम्र के शिशु को कानूनी रूप से गोद लेने हेतु सेवा के दौरान निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए एक बार अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है:

- (i) केवल एक शिशु गोद लेने हेतु अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।
- (ii) शिशु उचित कानूनी प्रक्रिया से गोद लिया जाना चाहिए तथा कर्मचारी को ऐसे अवकाश की स्वीकृति हेतु बैंक को दत्तक विलेख प्रस्तुत करना होगा।
- (iii) जन्म देने वाली मां को उन मामलों में भी छुट्टी मिलेगी जहां बच्चे का जन्म सरोगेसी के माध्यम से हुआ है, और
- (iv) समग्र सेवा अवधि के दौरान 12 महीने की कुल पात्रता में अवकाश लिया जा सकता है।

- (3) दिनांक 25 मई 2015 से, 12 महीने की समग्र अवधि के भीतर, बच्चेदानी को निकालने के मामले में भी अधिकतम 60 दिनों तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

- (4) मातृत्व अवकाश, जो कि वास्तविक वेतन पर होगा, किसी महिला अधिकारी को किसी एक अवसर पर 6 महीने से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा और उनकी समग्र सेवा अवधि के दौरान 12 महीने के लिए स्वीकृत किया जा सकता है।

बशर्ते कि 12 माह की समग्र अवधि में गर्भश्राव, गर्भपात या मेडिकल तौर पर गर्भपात कराने की स्थिति में अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

- (5) 1 जून 2015 से दो जीवित बच्चों तक वाले पुरुष कर्मचारी अपनी पत्नी की प्रसूति के दौरान 15 दिनों के पितृत्व अवकाश के लिए पात्र होंगे। यह अवकाश आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी अन्य अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है।

बशर्ते कि इस अवकाश के लिए बच्चे की डिलीवरी की तारीख से 15 दिन पहले या 6 महीने तक आवेदन किया जा सकता है।

14. कथित विनियम के विनियमन 38 के लिए निम्नलिखित उप-विनियमन प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा:-

“(38) अवकाश का व्यपगत (लैप्स) होना: निम्नलिखित को शामिल करते हुए, अधिकारी के त्यागपत्र, सेवा निवृत्ति,

मृत्यु, डिस्चार्ज, बर्खास्तगी या सेवा समाप्ति पर उसके समस्त अवकाश व्यपगत हो जाएंगे.”

बशर्ते बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाला अधिकारी किसी भी अवधि के लिए अपने द्वारा संचित अर्जित अवकाश, जो अधिकतम 240 होंगे, की परिलब्धियों की समान राशि के बराबर राशि के भुगतान का पात्र होगा.

बशर्ते यह भी कि यदि किसी अधिकारी को दंडस्वरूप अनिवार्य सेवा निवृत्त किया गया है, वह किसी भी अवधि के लिए अपने द्वारा संचित अर्जित अवकाश जो अधिकतम 240 होंगे, की परिलब्धियों की कुल राशि के बराबर राशि के भुगतान के पात्र होंगे.

बशर्ते यह भी कि यदि अधिकारी की सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु तारीख को उसके खाते में निहित अर्जित अवकाश, जो 240 से अधिक न हो, के परिलब्धियों के समकक्ष राशि उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को देय होगी.

बशर्ते यह भी कि विनियमन 20 के उप-विनियम (2) के अनुसार उचित नोटिस देने के पश्चात् 01.04.2001 को या उसके बाद बैंक सेवा से त्याग पत्र देने वाले अधिकारी को सेवा की समाप्ति की तारीख को निहित ऐसे अवकाश के आधे अवकाश, जो 120 दिनों से अधिक न हो, के नकदीकरण का पात्र होगा.

15. कथित विनियमन के विनियमन 41 के अनुसार;

(i) उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित उप-विनियमन प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा:-

“(1) 1 नवंबर 2012 को और से, जब भी किसी अधिकारी को कार्यालयीन उद्देश्य से यात्रा करनी होगी, ऐसी स्थिति में निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे, यथा:-

(ए) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी का अधिकारी ट्रेन द्वारा प्रथम श्रेणी अथवा 2टीयर एसी स्लीपर से यात्रा करने के लिए पात्र है.

वह एयर (इकॉनमी) द्वारा यात्रा करने के लिए पात्र होगा बशर्ते कि व्यावसायिक आकस्मिकताओं अथवा लोक हित को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई हो;

(बी) मध्यम प्रबंधन श्रेणी का अधिकारी ट्रेन द्वारा प्रथम श्रेणी अथवा एसी 2 टीयर स्लीपर से यात्रा के लिए पात्र है.

वह एयर (इकॉनमी श्रेणी) द्वारा यात्रा करने के लिए पात्र होगा बशर्ते कि यात्रा की जाने वाली दूरी 1000 किलोमीटर से अधिक हो.

वह कम दूरी के लिए भी एयर (इकॉनमी श्रेणी) से यात्रा कर सकता है बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यावसायिक आकस्मिकताओं अथवा लोक हित के संदर्भ में यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई हो.

(सी) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी अथवा उच्च कार्यपालक श्रेणी का अधिकारी ट्रेन द्वारा एसी प्रथम श्रेणी अथवा एयर (इकॉनमी श्रेणी) से यात्रा करने के लिए पात्र है;

(डी) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी अथवा उच्च कार्यपालक श्रेणी का अधिकारी ऐसी जगह जो एयर अथवा रेल से नहीं जुड़ी हुई है ऐसे स्थान पर कार से यात्रा करने के लिए पात्र हैं बशर्ते कि दूरी 500 किलोमीटर से अधिक ना हो;

यदि दो स्थानों के बीच की अधिकतम दूरी एयर अथवा रेल द्वारा तय की जा सकती है तो सामान्यतः केवल शेष दूरी कार द्वारा तय की जाए.

(ई) व्यावसायिक आकस्मिकताओं को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई भी अन्य अधिकारी को, उसके वाहन अथवा टैक्सी या बैंक के वाहन से यात्रा के लिए अनुमति दी जा सकती है.

(एफ) किसी भी श्रेणी अथवा वेतनमान का अधिकारी ऐसी जगह जो सड़क अथवा एयर या रेल से जुड़ा न हो, जल परिवहन के डिलक्स केबिन श्रेणी से यात्रा करने के लिए पात्र होगा.

(ii) उप विनियमन (4) में धारा (ए) और (बी) के लिए निम्नलिखित धाराओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्

“(ए) 01.06.2015 से तथा इसके पश्चात् नीचे दी गई सारणी के कॉलम 1 में उल्लिखित श्रेणी/ वेतनमान का अधिकारी सापेक्ष कॉलम 2 में उल्लिखित तदनुसूची दरों से विराम भत्ता पाने के लिए पात्र होगा:

अधिकारियों की श्रेणी / वेतनमान	महानगर (रु.)	प्रमुख 'ए' वर्ग के शहर (रु.)	क्षेत्र I (रु.)	अन्य स्थान (रु.)
(1)	(2)			
वेतनमान VI तथा उससे ऊपर के अधिकारी	1800	1300	1100	950
वेतनमान IV तथा V के अधिकारी	1500	1300	1100	950
वेतनमान I / II / III के अधिकारी	1300	1100	950	800

बशर्ते कि जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि आठ घंटे से कम है लेकिन चार घंटे से अधिक है, विराम भत्ता उपर्युक्त दरों का आधा देय होगा।

स्पष्टीकरण: विराम भत्ता की गणना के उद्देश्य से "दैनिक" का अर्थ है 24 घंटे की प्रत्येक अवधि या उसकी कोई आंशिक अवधि जोकि एयर द्वारा यात्रा किए जाने की स्थिति में प्रस्थान होने के लिए रिपोर्टिंग के समय से और अन्य मामलों में प्रस्थान के समय से लेकर आगमन के वास्तविक समय तक को गणना में लिया जाएगा और जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि चौबीस - घंटे से कम है वहां "दैनिक" का अर्थ आठ घंटे से कम की अवधि नहीं होगी।

(बी) मार्च 2020 के 31 वें दिन को और उसके बाद से निम्न तालिका के कॉलम (1) में दर्शाए गए श्रेणी अथवा वेतनमान के अधिकारी को वास्तविक होटल व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकती है जोकि इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एक कमरे के प्रभार की राशि के सापेक्ष कॉलम (2) में दर्शाए गए स्टार श्रेणी के कमरे के प्रभार तक सीमिति है, जोकि निम्नानुसार है:

तालिका

अधिकारियों का श्रेणी / वेतनमान	ठहरने की पात्रता
(1)	(2)
वेतनमान - VI, VII एवं VIII	4 स्टार होटल
वेतनमान IV एवं V	3 स्टार होटल
वेतनमान II एवं III	2 स्टार होटल (बिना वातानुकूलित)
वेतनमान - I	1 स्टार होटल (बिना वातानुकूलित)

बशर्ते कि केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसरण में निदेशक मंडल प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक अतिरिक्त सीमा को विनिर्दिष्ट कर सकता है।

16. कथित विनियम के विनियम 42 में, उप-विनियम (3) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(3) 01 जून, 2015 को और उसके बाद, किसी अधिकारी के स्थानांतरण होने पर निम्नलिखित तालिका में दर्शाए अनुसार वह पैकिंग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा, आदि से जुड़े खर्चों के लिए एकमुश्त राशि के लिए पात्र होगा, अर्थात्:—

तालिका

श्रेणी/ वेतनमान	राशि
(1)	(2)
उच्च कार्यपालक एवं वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी (वेतनमान IV और उससे अधिक के अधिकारी)	रु. 20,000
मध्य प्रबंधन एवं कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी (वेतनमान III तक के अधिकारी)	रु. 15,000”

17. कथित विनियम के विनियम 44 में, उप-विनियम (3) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(3) चार वर्षों के प्रत्येक खण्ड के दौरान अधिकारी दो वर्षों के प्रत्येक खण्ड में एक बार अपने गृहनगर (होमटाउन) की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा सुविधा का पात्र होगा।

बशर्ते कि वह दो वर्षों के एक खण्ड में अपने गृहनगर तथा दूसरे खण्ड में भारत में किसी भी स्थान की सबसे कम दूरी के मार्ग से यात्रा कर सकता है।

बशर्ते यह भी कि दिनांक 01 जून 2015 से विकल्पतः अधिकारी चार वर्ष या दो वर्ष के खण्ड में अपना विकल्प देकर, जो भी मामला हो, अपनी अवकाश यात्रा सुविधा को अभ्यर्पित तथा नकदीकरण करा सकता है (गृहनगर की यात्रा के अतिरिक्त), ऐसी स्थिति में, कनिष्ठ प्रबन्धन श्रेणी/ वेतनमान I तथा मध्यम प्रबन्धन श्रेणी/ वेतनमान II एवं III के अधिकारी 4500 किलोमीटर (एक तरफ) की दूरी तक तथा उच्च प्रबन्धन श्रेणी/ वेतनमान IV तथा इससे ऊपर के अधिकारी 5500 किलोमीटर तक (एक तरफ), रेल की यात्रा श्रेणी, जिसके लिए वे पात्र हैं, के कुल किराए की राशि प्राप्त कर सकते हैं।

बशर्ते यह कि दिनांक 01 जून 2015 से अवकाश यात्रा सुविधा के नकदीकरण का विकल्प देने वाला अधिकारी, जिस खण्ड में यह नकदीकरण किया गया है, उसमें अपने व अपने परिवार के लिए दावा कर सकता है। एलएफसी के नकदीकरण के दौरान अवकाश यात्रा सुविधा लेते समय अर्जित अवकाश को नकदीकरण कराने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

(3ए) वह माध्यम तथा श्रेणी जिसके द्वारा अधिकारी अवकाश यात्रा सुविधा ले रहा है सामान्यतः उस के समान होगी जिसके लिए अधिकारी स्थानांतरण होने पर सामान्य यात्रा के लिए पात्र है तथा अधिकारी द्वारा ली जाने वाली अवकाश यात्रा सुविधा के लिए अन्य नियम व शर्तें निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णयों पर आधारित होंगी।

बशर्ते दिनांक 1 मई 2010 से अवकाश यात्रा सुविधा लेने के दौरान कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I अधिकारी सबसे कम किराया वाले इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा करने के लिए पात्र होगा, जिसमें प्रतिपूर्ति वास्तविक किराया या ट्रेन से एसी प्रथम श्रेणी से तय की गई दूरी का किराया, जो भी कम हो, देय होगा। जहां दूरी 1000 किलोमीटर से कम है, वहां अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ लेते समय मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II और मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III के अधिकारी पर वही नियम लागू होंगे।

18. कथित विनियम की अनुसूची के लिए निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“अनुसूची”

[विनियम 23(2) देखें]

01 नवंबर 2012 से अधिकारी निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट अनुसार विशेष क्षेत्र भत्ते के लिए पात्र होंगे, जब तक कि वे पूरी तरह से या आंशिक रूप से वापस नहीं लिए जाते या संशोधित नहीं किए जाते, अर्थात्:-

तालिका

क्र. सं.	क्षेत्र	भत्ते (रुपए में)	
		रु. 24,000 से कम वेतन	रु. 24,000 से अधिक वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मिजोरम		
	क) मिजोरम का चमटुईपुई जिला तथा मिजोरम के लुंगलेई जिले के लुंगलई शहर से 25 किमी से अधिक दूरी वाले क्षेत्र	2000	2600
	ख) पूरे लुंगलेई जिले में, लुंगलेई शहर से 25 किमी से दूर वाले क्षेत्र को छोड़कर	1600	2100

	ग) मिजोरम का पूरा आइजोल जिला	1200	1500
2.	नागालैंड	1600	2100
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क) उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लघु अंडमान, निकोबार और नाकोंडम द्वीप समूह ख) दक्षिण अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)	2000 1600	2600 2100
4.	सिक्किम	2000	2600
5.	लक्षद्वीप द्वीप समूह	2000	2600
6.	असम	320	400
7.	मेघालय	320	400
8.	त्रिपुरा क) त्रिपुरा के कठिन क्षेत्र ख) कठिन क्षेत्रों को छोड़कर पूरा त्रिपुरा	1600 1200	2100 1500
9.	मणिपुर	1200	1500
10.	अरुणाचल प्रदेश क) अरुणाचल प्रदेश के कठिन क्षेत्र ख) कठिन क्षेत्रों के अलावा समस्त अरुणाचल प्रदेश	2000 1600	2600 2100
11.	जम्मू और कश्मीर ए) कठुआ जिला : नियाबतबानी, लोही, मलहार और मल्लोड़ी बी) उधमपुर जिला : 1. दादू बसंतगढ़, लेंडर भमाग इलाका, भाग 2(बी) में शामिल को छोड़कर 2. कम्बन की ओर से गोयल तथा केसई की ओर से अरदास तक के क्षेत्र सी) डोडा जिला : पाडेर के इलाके और किश्तवार तहसील में नियाबत नौगाम डी) लेह जिला : जिले के सभी स्थान ई) बारामुला जिला 1) समस्त गुरेज-नियाबत, तंगदार सब डिविजन तथा केरन इलाका 2) मचिल फ) पुंछ तथा राजौरी जिला: पुंछ और राजौरी नगरों को छोड़कर पुंछ और राजौरी जिले के अन्य क्षेत्र तथा दो जिलों में सुंदरबनी तथा अन्य शहरी क्षेत्र	2000 2000 1600 2000 2000 2000 1600 1200	2600 2600 2100 2600 2600 2600 2100 1500

	जी) उपरोक्त (ए) से (एफ) के अलावा अन्य क्षेत्र जो वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 किमी से कम दूरी पर है या वह क्षेत्र जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा उनके स्टाफ के लिए बॉर्डर भत्ते के रूप में घोषित किया जाता है.	1200	1500
12.	हिमाचल प्रदेश (1) चंबा जिला (ए) पांगी तहसील, भरमौर तहसील, पंचायत : बड़गांव, बाजोल, देवल कुम्ती, नयागाम और टुंडा, गांव: ग्राम पंचायत जगत का घाटू, ग्राम पंचायत चौहटा का कनारसी (बी) भारमौर तहसील, उक्त (ए) में शामिल पंचायतों और गांव को छोड़कर (सी) भलियाट तहसील में झंडरू पंचायत, चुराह तहसील, डलहौजी शहर (मूल बानीखेत सहित)	2000 1600 1200	2600 2100 1500
	2. किन्नौर जिला: i) असरंग, चितकुल और हंगोकुनो/चारंग पंचायत, छोटा खंबा, नथपा, और रूपी की ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करते हुए 15/20 क्षेत्र, पूह उप विभाग, उपरोक्त निर्धारित पंचायत क्षेत्र को छोड़कर ii) उपरोक्त (i) में शामिल क्षेत्रों को छोड़कर समग्र जिला	2000 1600	2600 2100
	3. कुलु जिला: (i) खरगा, कुश्वर और सर्गा की ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करते हुए निर्मद तहसील के 15/20 क्षेत्र (ii) बाहरी-सेरज (निर्मद तहसील के जकात खाना और बरो गांवों को छोड़कर) और संपूर्ण जिला (बाहरी सेरज क्षेत्र और पंडरबीस के परगना को छोड़कर परंतु निर्मद तहसील के जगत खाना और बरो को सम्मिलित करते हुए)	2000 1200	2600 1500
	4. लाहौत और स्पिति जिला : लाहौत और स्पिति का संपूर्ण क्षेत्र	2000	2600
	5. शिमला जिला : i) कूट, लबाना-सादना, सरपरा और चड़ी बरान्दा की पंचायतों को सम्मिलित करते हुए रामपुर तहसील के 15/20 क्षेत्र ii) दोदरा कवर तहसील, रामपुर में दारकली की ग्राम पंचायत, काशपथ तहसील और मुनीश, परगना सराहन की घोरी चौबीस iii) चोपाल तहसील और घोरीस, पुंजगांव, पत्सनी, परगना साराह की नौबीस और तीन कोटी, तकलेश क्षेत्र की देओठी ग्राम पंचायत, परगना बाराबीस, रामपुर तहसील की परगना रामपुर के कस्बा रामपुर और घोरी नोग, शिमला टाउन और उसके नगर परिसर (ढालली,जातोग, कासुम्भि, माशोबरा, तारादेवी तथा तूतू)	2000 1600 1200	2600 2100 1500

	<p>6. कांगड़ा जिला:</p> <p>i) बारा भांगल और छोटा भांगल के क्षेत्र</p> <p>1600</p> <p>2100</p> <p>ii) कांगड़ा जिले की धरमशाला टाउन और म्युनिसिपल सीमा के बाहर परंतु धरमशाला टाउन में सम्मिलित स्थित निम्न कार्यालय: वुमैस आईटीआई, दारी, मिक्केनिकल वर्कशॉप, रामनगर, चाइल्ड वेलफेयर और टाउन और कंट्री प्लानिंग कार्यालय, साकोह, लोवर साकोह की सीआरएसएफ कार्यालय, कांगड़ा मिल्क सप्लाय योजना, डुगैर, एचाअरटीसी वर्कशॉप, साधेर, जोनल मलेरिया कार्यालय, दारी, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन कार्यालय, शामनगर, टी फैक्टरी, दारी, आईपीएच उपविभाग, दान, सेटलमेंट कार्यालय, शामनगर, हिनवा प्रोजेक्ट, शामनगर</p> <p>1200</p> <p>1500</p> <p>एचपीकेवीवी कैम्पस, पालमपुर सहित कांगड़ा जिले का पालमपुर टाउन, और म्युनिसिपल सीमा के बाहर परंतु पालमपुर टाउन में सम्मिलित स्थित निम्न कार्यालय: एचपी कृषि विश्वविद्यालय कैम्पस, कैटल डेवेलपमेंट कार्यालय/जर्सी फार्म, बनौरी, सेरिकल्चर कार्यालय/इंडो -जर्मन एग्रीकल्चर वर्कशॉप/एचपीपीडब्ल्यूडी डिविजन, इलेक्ट्रिकल सब डिविजन, लोहना, डीपीओ कॉर्पोरेशन, बुंदला, इलेक्ट्रिकल एचपीएसईई डिविजन, घुमगर</p>		
	<p>7. मंडी जिला:</p> <p>जोगिंदरनगर तहसील की छुहर वैली, बागरा के थुनाग तहसील की पंचायतें, चातरी, छोटधर, गारगुदसहिन, गाढ़ू, गरयास, जनजेहली, जरयार, जोहर, कलहानी, कलवान, खोलनाल, लोथ, सिल्लीबागी, सोमाचन, थाचधर, ताची, थाना, धरमपुर ब्लॉक की पंचायतें -बिंगा, कामलाह, सकलाना, तन्यार और ताराखोलह, करसोग तहसील की पंचायतें बलीधर, बागरा, गोपालपुर, खाजोल, महोग, मेहूडी, मंज, पेखी, सैंज, साराहन और तेबान, सुंदरनगर तहसील की पंचायतें - बोही, बटवारा, धन्यारा, पौरा कोठी, सेरी और शोजा</p>	1200	1500
	<p>8. सिरमौर जिला:</p> <p>बानी, बाखली (पाचड़ तहसील), भारोग भेनारी (पाओंता तहसील), बिरला (नाहन तहसील), डिब्बर (पाछड़ तहसील) और थाना कासोगा (नाहन तहसील) और थांसगिरी ट्रैक्ट की पंचायतें</p>	1200	1500
	<p>9. सोलन जिला :</p> <p>मंगल पंचायत</p>	1200	1500
	<p>10. उक्त 1 से 9 मद में न सम्मिलित किए गए हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्र</p>	320	400
13.	<p>उत्तर प्रदेश:</p> <p>चमोली, पित्तोरगढ़ और उत्तर काशी जिले के तहत क्षेत्र:</p>	2000	2600
14.	<p>उत्तराखण्ड:</p> <p>चमोली, पित्तोरगढ़, उत्तर काशी, रुद्रप्रयाग और चांपावत जिलों के तहत क्षेत्र</p>	2000	2600"

विवरणात्मक ज्ञापन

इन विनियमों में दिए गए पूर्वव्यापी प्रभाव बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों के लिए वेतन और अन्य भत्ते और अन्य लाभों से संबंधित हैं और अनिवार्य रूप से लाभकारी कानून हैं. अतः इन विनियमों के उक्त प्रावधानों को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से इस तरह के पूर्वव्यापी प्रभाव को लागू करने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.

दविंदर पाल ग्रोवर, महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./524/19]

नोट: संशोधन विनियम भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में निम्नलिखित संशोधनों के माध्यम से प्रकाशित किए गए, यथा:-

क्र. सं.	बैंक के परिपत्र	सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि
1	एचओ:एसटीएफ:ए/10/13:455 दिनांक 07-03-1988	26-03-1988
2	एचओ:एसटीएफ:ए/10/13:456 दिनांक 07-03-1988	26-03-1988
3	एचओ:एसटीएफ:ए/10/15:73 दिनांक 21-01-1989	25-02-1989
4	एचओ:एसटीएफ:ए/10/15:267 दिनांक 01-03-1989	01-04-1989
5	एचओ:एसटीएफ:ए/10/10:792 दिनांक 10-05-1990	16-06-1990
6	एचओ:ओएसआर&आईआर:ए/10/14:1030 दिनांक 21-07-1993	25-09-1993
7	एचओ:ओएसआर&आईआर:ए/10/16:1029 दिनांक 21-07-1989	25-09-1993
8	एचओ:ओएसआर&आईआर:ए/10/9:657 दिनांक 05-06-1993	24-07-1993
9	एचओ:ओएसआर&आईआर:ए/10/14:704 दिनांक 30-04-1994	16-07-1994
10	एचओ:ओएसआर&आईआर:ए/6/9:2828 दिनांक 02-12-1996	22-02-1997
11	एचओ:ओएसआर&आईआर:ए/12/9:2902 दिनांक 11-12-1999	14-01-2000
12	एचओ:ओएसआर&आईआर:ए/10/18:1057 दिनांक 21-06-2000	29-07-2000
13	एचओ:ओएसआर&आईआर:ए/10/20 दिनांक 10-12-2002	04-01-2003
14	बीसीसी:एचआरएम:98 दिनांक 20-02-2006	07-04-2006
15	एचओ:ओएसआर&आईआर:ए/10:150 27-11-2006	02-01-2007
16	दिनांक 23-12-2010	22-01-2011
17	एचओ:एचआर-ओपीएस:ओएसआर&आईआर:282 दिनांक 15-11-2017	12-12-2017

BANK OF BARODA
(HRM Department)
(BARODA CORPORATE CENTRE)
NOTIFICATION

Mumbai, the 31st March, 2020

No. BCC:HRM:EXE:112/274.—In exercise of powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Bank of Baroda, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby make the following regulations further to amend the Bank of Baroda (Officers') Service Regulations, 1979, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Bank of Baroda (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2020.

(2) Save as provided in these regulations, they shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of November, 2012.

2. In the Bank of Baroda (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3, for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:—

“(f) “family” means the spouse of the officer, wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children), wholly dependent physically and mentally challenged brother or sister with forty per cent or more disability, widowed daughters and dependent divorced or separated daughters, sisters including unmarried or divorced or abandoned or separated from husband or widowed sisters, and parents wholly dependent on the officer and in the case of a married female officer may include her natural parents or parents-in-law, but not both.

Explanation.— “wholly dependent” shall mean such member of the family having an income not exceeding Rs.10,000 per month and where the wholly dependent family member are parents, the income of any parent or aggregate income of both the parents if exceeds Rs.10,000 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer;”.

3. In regulation 4 of the said regulations, for sub-regulation (6), the following sub-regulations shall be inserted, namely:—

“(6) With effect from the 1st November, 2012, the scales of pay specified against each grade shall be as under:

(a) Top Executive Grade

Scale VII = Rs.76520 – 2120/4 – 85000

Scale VI = Rs.68680 – 1960/4 – 76520

(b) Senior Management Grade

Scale V = Rs.59170 – 1650/2 – 62470 – 1800/2 – 66070

Scale IV = Rs.50030 – 1460/4 – 55870 – 1650/2 – 59170

(c) Middle Management Grade

Scale III = Rs.42020 – 1310/5 – 48570 – 1460/2 – 51490

Scale II = Rs.31705 – 1145/1 – 32850 – 1310/10 – 45950

(d) Junior Management Grade

Scale I = Rs.23700 – 980/7 – 30560 – 1145/2 – 32850 – 1310/7 – 42020

Explanation.—Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on 31st October, 2012 shall be fitted in the scale of pay as set out in this sub-regulation as on 1st November, 2012 on stage-to-stage basis or the corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual.

(7) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3), (4), (5) and (6) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.

(8) With effect from the 1st day of November, 2012, officers shall be paid Special Allowance as under:

Scale I–III = 7.75% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV–V = 10% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI–VII = 11% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

(9) On and from 31st day of March, 2020, the Scale of Pay and Special Allowance for the post of Chief General Manager in Top Executive Grade shall be as under:

(A) Top Executive Grade

Scale VIII = Rs.1,03,000 – 2,700/3 – 1,11,100 – 2,800/1 – 1,13,900

(B) Special Allowance

Scale VIII = 11% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon:

Provided that nothing in this sub-regulation shall be construed as requiring the Bank to have at all times officers serving in this grade.

Note: The Special Allowance referred to in sub-regulations (8) and (9) with applicable Dearness Allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, such as pension including New Pension Scheme, Provident Fund and Gratuity.”.

4. In regulation 5 of the said regulations,—

(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1) Subject to the provisions of sub-regulation (6) of regulation 4, on and from the 1st November, 2012, the increments shall be granted subject to the following, namely:—

- (a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (6) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;
- (b) one year after reaching the maximum in their respective Scales, officers in Scale I and Scale II, shall be granted further increments including stagnation increment in the next higher Scale only as specified in clause (c) below subject to their crossing the efficiency bar;
- (c) officers in Junior Management Grade Scale I who have moved to Middle Management Grade Scale II in terms of clause (b) after reaching maximum of the higher Scale, shall be eligible for four stagnation increments for every three completed years of service of which the first two shall be Rs. 1310 each and next two, Rs. 1460 each;
- (d) officers in Middle Management Grade Scale II who have moved to Middle Management Grade Scale III in terms of clause (b) after reaching maximum of higher scale shall be eligible for three stagnation increments of Rs.1460/- each for every three completed years of service and a fourth stagnation increment of Rs. 1460/- two years after receipt of third stagnation increment:

Provided that officers who have completed two years or more after receipt of the third stagnation increment shall be granted the fourth stagnation increment with effect from the 1st day of May, 2015;

- (e) officers in substantive Middle Management Grade Scale III (those recruited in or promoted to Middle Management Grade Scale III) shall be eligible for three stagnation increments of Rs. 1460/- each for every three completed years of service and fourth stagnation increment of Rs. 1460/- to officers who have completed two years or more after releasing third stagnation increment as on 1st May, 2015 and a fifth stagnation increment of Rs. 1460/- two years after receipt of fourth stagnation increment provided that the officers who

have completed two years after receipt of the fourth stagnation increment shall be granted the fifth stagnation increment with effect from 1st May, 2015;

- (f) officers in Senior Management Grade Scale–IV shall be eligible for one stagnation increment of Rs. 1650/- three years after reaching the maximum of scale with effect from 1st May, 2015:

Provided that such increment shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

Explanation.—Grant of such increments in the next higher Scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.”;

- (ii) in sub-regulation (2), in the *Explanation*, after clause (f) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:—

“(g) On and from the 1st day of November, 2012, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the Table below:

TABLE

(1)	(2)
Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers – Part I	Rs. 670/- per month, one year after reaching maximum of the scale
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs. 670/- per month, one year after reaching maximum of the scale (ii) Rs.1680/- per month, two years after reaching maximum of the scale:

Provided that an officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay”;

- (iii) In sub-regulation (3), after the table under clause (e), the following shall be inserted, namely:—

“(f) On and from the 1st November, 2012, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:

TABLE

Increment component (Rs.)	Dearness Allowance as on 01.11.2012 on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where Bank's accommodation is provided (Rs.)
(1)	(2)	(3)
1310	143	1453
1460	159	1619
1650	180	1830
1800	196	1996
1960	214	2174
2120	231	2351

Note:

(i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (3) of the tables in clauses (b), (c), (d), (e) and (f) of this sub-regulation shall be payable to those officers who are provided with Bank's accommodation.

(ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (1) and (2) of the table under clause (f) and House Rent Allowance drawn by the concerned officer when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulations (2), (3), (4), (5) and (6) of regulation 4 is earned.

(iii) Only officers who were in the service of the Bank on or before 1st November, 1993 shall be eligible for Fixed Personal Pay one year after reaching the maximum scale of pay they are placed.

(iv) On and from the 1st November, 1999 there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as in Explanation (c) of sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:

Provided that where any installment of Professional Qualification Pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after the 1st November, 1999, it shall be released to the officer on and from that date and second installment of Professional Qualification Pay, if any, shall be released on the 1st November, 2000.

(v) The increment component of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.

(vi) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) of this sub-regulation shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d), (e) or (f) above, one year after reaching the maximum of the scale.

(g) On and from the 31st day of March 2020, other things being equal, the Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance, if any, for the post of Chief General Manager in Top Executive Grade Scale-VIII shall be at the rates given in the table below and shall remain frozen for the entire period of service:

TABLE

Increment component (Rs.)	Dearness Allowance on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
(1)	(2)	(3)
2800	305	3105

5. For regulation 7, the following regulation shall be substituted, namely:—

“7. Categorisation.— (1) On and from the 31st day of March 2020 and subject to the provisions of regulation 6, the various posts of officers in the Bank shall be categorized as specified in the table below:

TABLE

POSTS	GRADE or SCALE IN WHICH PLACED
Chief General Manager	Top Executive Grade Scale-VIII
General Manager	Top Executive Grade Scale-VII
Deputy General Manager	Top Executive Grade Scale-VI
Assistant General Manager	Senior Management Grade Scale-V
Chief Manager	Senior Management Grade Scale-IV
Senior Manager	Middle Management Grade Scale-III
Manager	Middle Management Grade Scale-II
Officer or Dy. Manager	Junior Management Grade Scale-I

(2) If any difficulty or anomaly arises out of the above categorization, the same shall be referred to a Committee consisting of the Managing Director and Chief Executive Officer and such other person or persons as may be appointed by the Central Government for this purpose, for its decision.”.

6. In regulation 21 of the said regulations, after sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(6) On and from the 1st day of November, 2012, Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 4440 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.10% of pay.

Explanation.— For the purposes of this sub-regulation,—

- (a) “pay” for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments plus Special Allowance;
- (b) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in clauses (c), (d), (e), (f) and (g) to the explanation in sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for Dearness Allowance.”.

7. In regulation 22 of the said regulations,—

(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1) On and from the 1st day of November, 2012,—

- (a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 0.75 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;
- (b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely:—

TABLE

Place of work	House Rent Allowance
(1)	(2)
(i) Major “A” Class Cities and Project Area Centres in Group A	9.0% of Pay
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B and State of Goa	8.0% of Pay
(iii) Other places	7.0% of Pay:

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 0.75 per cent of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (2) of the above Table.

Note: The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall also be restricted to 150 per cent of the House Rent Allowance as hitherto.”;

(ii) sub-regulation (2) shall be omitted.”.

8. In regulation 23 of the said regulations,—

(A) for sub-regulations (1), (2), (3), (4) and (5), the following sub-regulations shall be substituted, namely:—

“(1) On and from the 1st day of November, 2012, if an officer is serving in a place mentioned in column (1) of the table below, a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in column (2) thereof against that place shall be payable:—

TABLE

Places	Rate
(1)	(2)
(i) Places in Area I and in the State of Goa	4% of Basic Pay subject to a maximum of Rs.870 per month
(ii) Places with population of five lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Puducherry and Port Blair	3% of Basic Pay subject to a maximum of Rs.600 per month.

- (2) On and from the 1st day of November, 2012, the rates of special areas allowances shall be as specified in the Schedule to these regulations.
- (3) On and from the 1st day of November, 2012, if an officer is serving in an area specified as Project Area falling in Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.400/- per month or Rs.350/- per month according to the classification of area as Group A or Group B respectively.
- (4) On and from the 1st day of June, 2015, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs. 1100/- per month from the date he reports to the latter place up to the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.
- (5) On and from the 1st day of June, 2015, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent of pay subject to a maximum of Rs.4000 per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank's service at that place:

Provided that where he is deputed to an organization which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent of his pay subject to a maximum of Rs.2000/- per month:

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the Bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4 per cent of his pay subject to a maximum of Rs.2000/- per month.”;

- (B) for sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(8) On and from the 1st day of November 2012, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.200 per month.”;

- (C) in sub-regulation(10),—

- (a) for the figures, letters and words “1st day of November 2007”, the figures, letters and words “1st day of November, 2012” shall be substituted;
- (b) for the Table, the following table shall be substituted, namely:—

“TABLE

Place	Rate
(1)	(2)
(i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs. 750 per month
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2.5% of pay subject to a maximum of Rs.1000 per month
(iii) Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.2000 per month”.

9. In regulation 24 of the said regulations,—

(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1) On and from the 1st day of November, 2012, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer’s own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely:—

TABLE

Grade	Maximum limit of reimbursement
(1)	(2)
Junior Management and Middle Management Grade	Rs. 8000 per annum or the amount incurred whichever is less
Senior Management and Top Executive Grade	Rs. 9050 per annum or the amount incurred whichever is less

Note: (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above; or
(ii) for the year 2012, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November, 2012 and December, 2012.

(1A) An officer shall be eligible for Medical Insurance facility for self and his family, as per the terms and conditions specified by the Board.”.

10. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November, 2012, a sum equal to 0.75 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.15 per cent of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the Bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.”.

11. In regulation 33 of the said regulations, for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(4) On and from 1st June, 2015, Privilege Leave may be accumulated up to not more than 270 days except where leave has been applied and it has been refused:

Provided that encashment of Privilege Leave shall be restricted up to a maximum of 240 days:

Provided further that an officer desiring to avail Privilege Leave shall ordinarily give not less than 15 days notice of his intention to avail such leave.”.

12. In regulation 34 of the said regulations, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(4) On and from 1st June, 2015, Special Sick Leave up to 30 days may be granted to an officer once during his entire period of service for donation of kidney or organ.”.

13. In regulation 36 of the said regulations, for sub-regulations (2) and (3), the following sub-regulations shall be substituted, namely:—

“(2) With effect from the 25th May 2015, leave may also be granted once during service to a childless female officer for legally adopting a child who is below one year of age for a maximum period of six months subject to the following terms and conditions:—

- (i) leave will be granted for adoption of only one child;
- (ii) the adoption of a child should be through a proper legal process and the employee should produce the adoption deed to the Bank for sanctioning such leave;
- (iii) the leave shall also be available to biological mother in cases where the child is born through surrogacy; and
- (iv) the leave shall be availed within overall entitlement of twelve months during the entire period of service.

(3) With effect from the 25th May 2015, within the overall period of twelve months, leave may also be granted in case of hysterectomy up to a maximum of sixty days.

(4) Maternity leave, which shall be on substantive pay, shall be granted to a female officer for a period not exceeding six months on any one occasion and twelve months during the entire period of her service:

Provided that within the overall period of twelve months, leave may also be granted in case of miscarriage or abortion or Medical Termination of Pregnancy.

(5) With effect from 1st June 2015, male officers employees having up to two surviving children shall be eligible for fifteen days paternity leave during his wife’s confinement which may be combined with any other kind of leave except casual leave:

Provided that the leave shall be applied up to fifteen days before or up to six months from the date of delivery of the child.”.

14. For regulation 38 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:—

“(38) Lapse of Leave.— Save as provided below, all leave to the credit of an officer shall lapse on resignation, retirement, death, discharge, dismissal or termination:

Provided that where an officer retires from the Bank’s service, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments of any period, not exceeding 240 days of privilege leave that he had accumulated:

Provided further that where an officer has been compulsorily retired including as a measure of punishment, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to emoluments of any period, not exceeding 240 days of privilege leave that he has accumulated:

Provided also that where an officer dies while in service, there shall be payable to his legal representatives, a sum equivalent to the emoluments for the period not exceeding 240 days of privilege leave to his credit as on the date of his death:

Provided also that where an officer resigns from service on or after 1st April, 2001 after giving due notice as in sub-regulation (2) of regulation 20, he may be paid a sum equivalent to the emoluments in respect of privilege leave to the extent of half of such leave to his credit on the date of cessation of service, subject to a maximum of 120 days.”.

15. In regulation 41 of the said regulations,—

(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1) On and from 1st day of November 2012, wherever an officer is required to travel on duty, the following provisions shall apply, namely:—

(a) an Officer in Junior Management Grade is entitled to travel by 1st class or AC 2-tier Sleeper by train:

Provided that he may travel by air (economy class) if so permitted by Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest;

(b) an officer in Middle Management Grade is entitled to travel by 1st Class or AC2-tier Sleeper by train:

Provided that he may travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 1000 kilometers:

Provided further that he may travel by air (economy class) even for shorter distance if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest;

(c) an officer in Senior Management or Top Executive Grade is entitled to travel by AC 1st Class by train or by air (economy class);

(d) an officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 kilometers:

Provided that when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail only the rest of the distance should normally be covered by car;

(e) any other officer may be authorized by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxi or by the Bank's vehicle;

(f) an officer of any grade or scale shall be eligible to travel by water transport in deluxe cabin category between places not connected by road or air or rail.”;

(ii) in sub-regulation (4), for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:

“(a) On and from the 1st June, 2015, an officer in the Grades or Scales set out in column (1) of the table below shall be entitled to per diem Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely:—

TABLE

Grade/Scales of Officers	Metro (Rs.)	Major 'A' Class Cities (Rs.)	Area -1 (Rs.)	Other Places (Rs.)
(1)	(2)			
Officers in Scale VI and above	1800	1300	1100	950
Officers in Scale IV and V	1500	1300	1100	950
Officers in Scale I, II and III	1300	1100	950	800

Provided that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation: – For the purposes of computing Halting Allowance “per diem” shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, “per diem” shall mean a period of not less than eight hours.

(b) On and from the 31st day of March 2020, an Officer in the Grades or Scales set out in column (1) of the table below may be reimbursed the actual hotel expenses restricting to single room accommodation charges in India Tourism Development Corporation hotels of the corresponding star category set out in column (2) thereof, as under:

TABLE

GRADES / SCALES OF OFFICERS	ELIGIBILITY TO STAY
(1)	(2)
Scale-VI, VII and VIII	4 Star Hotel
Scale-IV and V	3 Star Hotel
Scale-II and III	2 Star Hotel (Non AC)
Scale-I	1 Star Hotel (Non AC)

Provided that the Board may specify the additional limit to be reimbursed in excess of the limits specified above, in accordance with the guidelines of the Central Government.”.

16. In regulation 42 of the said regulations, for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(3) On and from the 1st day of June, 2015, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the table below, namely:—

TABLE

Grade/Scale	Amount
(1)	(2)
Top Executive and Senior Management Grade (Officers in Scale IV and above)	Rs.20,000
Middle Management and Junior Management Grade (Officers up to Scale III)	Rs.15,000”

17. In regulation 44 of the said regulations, for sub-regulation (3), the following sub-regulations shall be substituted, namely:—

“(3) During each block of four years, an officer shall be eligible for leave travel concession for travel to his place of domicile once in each block of two years:

Provided that, he may travel in one block of two years to his place of domicile and in another block of two years to any place in India by the shortest route:

Provided further that with effect from 1st June, 2015, alternatively, an officer by exercising an option anytime during a four year block or two year block, as the case may be, surrender and encash his Leave Travel Concession (other than travel to place of domicile) upon which he shall be entitled to receive an amount equivalent to the eligible fare for the class of travel by train to which he is entitled up to a distance of 4,500 kilometers (one-way) for officers in JMG-Scale I and MMG-Scale II and III and 5,500 kilometers (one-way) for officers in SMG-Scale IV and above:

Provided also that with effect from 1st June, 2015, an officer opting to encash his Leave Travel Concession, shall prefer the claim for himself and his family members only once during the block in which such encashment is availed of and the facility of encashment of privilege leave while availing of Leave Travel Concession is also available while encashing the facility of Leave Travel Concession.

(3A) The mode and class by which an officer may avail of Leave Travel Concession shall be the same as the officer is normally entitled to travel on transfer and other terms and conditions subject to

which the Leave Travel Concession may be availed of by an officer, shall be as decided by the Board from time-to-time:

Provided that with effect from 1st May, 2010, an officer in Junior Management Grade Scale I while availing Leave Travel Concession shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement will be the actual fare or the fare applicable to AC 1st Class fare by train for the distance travelled whichever is less and the same rules shall apply when an Officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III while availing Leave Travel Concession where the distance is less than 1000 kilometers.”.

18. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely:—

“SCHEDULE

[See regulation 23(2)]

With effect from the 1st day of November, 2012, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:—

TABLE

Sl.No.	Area	Allowances (in rupees)	
		Pay below Rs. 24,000	Pay above Rs. 24,000
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mizoram		
	(a) Chimgtuipui District and areas beyond 25 kilometers from Lunglei Town in Lunglei District.	2000	2600
	(b) Entire Lunglei District excluding areas beyond 25 kilometers from Lunglei town.	1600	2100
	(c) Entire Aizawl District	1200	1500
2.	Nagaland	1600	2100
3.	Andaman and Nicobar Islands		
	(a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	2000	2600
	(b) South Andaman(including Port Blair)	1600	2100
4.	Sikkim	2000	2600
5.	Lakshadweep Islands	2000	2600
6.	Assam	320	400
7.	Meghalaya	320	400
8.	Tripura		
	(a) Difficult areas of Tripura	1600	2100
	(b) Throughout Tripura except difficult areas.	1200	1500

9.	Manipur	1200	1500
10.	Arunachal Pradesh		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	2000	2600
	(b) Throughout Arunachal Pradesh other than difficult areas.	1600	2100
11.	Jammu and Kashmir		
	(a) Kathua District: Niabat Bani, Lohi, Malhar and Machhodi	2000	2600
	(b) Udhampur District:		
	(i) DuduBasantgarh, Lander BhamagIllaqa, other than those included in Part 2(b).	2000	2600
	(ii) Areas up to Goel from Kamban Side and areas up to Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre.	1600	2100
	(c) Doda District: Illaquas of Padder and NiabatNowgam in Kishtwar Tehsil	2000	2600
	(d) Leh District: All places in the District	2000	2600
	(e) Barmulla District		
	(i) Entire Gurez– Nirabat , Tangdar Sub– Division and KeranIllaqua	2000	2600
	(ii) Matchill		
	(f) Poonch and Rajouri District:	1600	2100
	Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts.	1200	1500
	(g) Areas not included in items (a) to (f) above, but which are within the distance of 8 kilometers from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time–to–time by the State Government for their own staff.	1200	1500

12.	Himachal Pradesh		
	1. Chamba District		
	(a) Pangi Tehsil, Bharmour Tehsil, Panchayats: Badgaun, Bajol, DeolKugti, Nayagam and Tundah, Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata	2000	2600
	(b) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in (a) above.	1600	2100
	(c) Jhandru Panchayat in Bhatiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper).	1200	1500
	2. Kinnaur District:		
	(i) Asrang, Chitkul and Hango Kuno/Charang Panchayats, 15/20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Ruppi, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above.	2000	2600
	(ii) Entire District other than Areas included in (i) above.	1600	2100
	3. Kullu District:		
	(i) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	2000	2600
	(ii) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District excluding outer Saraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand).	1200	1500
	4. Lahaul and Spiti District:		
	Entire area of Lahaul and Spiti	2000	2600
	5. Shimla District:		
	(i) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda.	2000	2600

	<p>(ii) Dora–Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghorichaibis of Pargana Sarahan.</p> <p>(iii) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon , Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, kasba Rampur and Ghorinog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Simla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).</p>	1600	2100
	<p>(iii) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon , Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, kasba Rampur and Ghorinog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Simla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).</p>	1200	1500
	<p>6. Kangra District:</p> <p>(i) Areas of Bara Bhangal and Chhota Bhangal</p> <p>(ii) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town—Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiari, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H—Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Hinwa Project, Shamnagar.</p> <p>Palampur Town of Kangra District including HPKV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town—H.P.</p> <p>Krishi Vishwavidyalaya Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HESEE Division, Ghuggar.</p>	1600	2100
	<p>(ii) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town—Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiari, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H—Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Hinwa Project, Shamnagar.</p> <p>Palampur Town of Kangra District including HPKV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town—H.P.</p> <p>Krishi Vishwavidyalaya Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HESEE Division, Ghuggar.</p>	1200	1500
	<p>7. Mandi District:</p> <p>Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in Thunag Tehsil— of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gatoo, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block—Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil—Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil—Bohi, Batwara, Dhanyara, PauraKothi, Seri and Shoja.</p>	1200	1500

	8. Sirmaur District: Panchayats of Bani, Bakhali,(Pachhad Tehsil), Bharog Bheneri(Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber(Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil) and Thansgiri Tract	1200	1500
	9. Solan District MangalPanchayat	1200	1500
	10. Remaining areas of Himachal Pradesh not included in items (1) to (9) above.	320	400
13.	Uttar Pradesh Areas under Chamoli, Pithoragarh and Uttar Kashi Districts	2000	2600
15.	Uttarakhand Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat Districts.	2000	2600”

EXPLANATORY MEMORANDUM

The retrospective effect given in these regulations relate to the pay and other allowances and benefits to the officers of the Bank of Baroda and are essentially beneficial legislation. Hence, giving retrospective effect to the said provisions of these regulations will not adversely affect the interest of any person as a result of such retrospective application.

DEVINDER PAL GROVER, General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./524/19]

Note: The amendment regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4 *vide* following notifications, namely:—

Sl.No.	Bank's Circulation	Date of publication in official Gazette
1	HO:STF:A:10/13:455 dated 07-03-1988	26-03-1988
2	HO:STF:A:10/13:456 dated 07-03-1988	26-03-1988
3	HO:STF:A:10/15:73 dated 21-01-1989	25-02-1989
4	HO:STF:A:10/15:267 dated 01-03-1989	01-04-1989
5	HO:STF:A:10/10:792 dated 10-05-1990	16-06-1990
6	HO:OSR&IR:A/10/14:1030 dated 21-07-1993	25-09-1993
7	HO:OSR&IR:A/10/16:1029 dated 21-07-1989	25-09-1993
8	HO:OSR&IR:A/10/9:657 dated 05-06-1993	24-07-1993
9	HO:OSR&IR:A/10/14:704 dated 30-04-1994	16-07-1994
10	HO:OSR&IR:A/6/9:2828 dated 02-12-1996	22-02-1997

11	HO:OSR&IR:A/12/9:2902 dated 11-12-1999	14-01-2000
12	HO:OSR&IR:A/10/18:1057 dated 21-06-2000	29-07-2000
13	HO:OSR&IR:A/10/20 dated 10-12-2002	04-01-2003
14	BCC:HRM:98 dated 20-02-2006	07-04-2006
15	HO:OSR & IR :A:10:150 27-11-2006	02-01-2007
16	Dated 23-12-2010	22-01-2011
17	HO:HR-OPS:OSR&IR:282 dated 15-11-2017	12-12-2017